



श्री कलराज मिश्र

माननीय राज्यपाल,
राजस्थान का उद्बोधन

प्रेस वार्ता

दिनांक : 9 सितम्बर, 2020

समय : दोपहर 12.00 बजे

स्थान : राजभवन, जयपुर

आप सभी मीडिया के प्रतिनिधिगण का मैं अभिवादन करता हूँ। इस ऑनलाइन प्लेटफार्म से जुड़े सभी पत्रकारगण एवं छायाकार बन्धुओं को मेरा नमस्कार।

राजस्थान प्रदेश के राज्यपाल के रूप में मैंने 9 सितम्बर, 2019 को कार्यभार ग्रहण किया। मुझे आज यहां एक वर्ष पूरा हो गया है। इस संबंध में राजभवन द्वारा एक पुस्तक नई सोच-नए आयाम का प्रकाशन किया गया है, जिसकी ई-प्रति आप सभी को भिजवा दी गई है।

राजस्थान राज्य से, यहां के लोगों से, यहां की गतिविधियों से पहले से ही, मैं परिचित हूँ। अब राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर मुझे यहां कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संवैधानिक मर्यादाओं में रह कर मैं राज्य हित में और लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ।

राजस्थान वीरों की भूमि है, इसलिए अमर जवान ज्योति पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करके मैंने अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों की शुरुआत की।

जब मुझे पता चला कि कोटा संभाग में बाढ़ आई हुई है, तो मैंने तत्काल एरियल सर्वेक्षण किया। बचाव एवं राहत कार्यों का जायजा लिया। राजभवन में राज्यपाल राहत कोष है। मैंने इस कोष की जानकारी ली और उसमें से पचास लाख रुपये की राशि जल भराव क्षेत्रों के लिए प्रदान की। राज्यपाल राहत कोष उन लोगों की मदद करने में सक्षम है, जिनको कहीं से सहायता नहीं मिल पाती है। राज्यपाल राहत कोष के उद्देश्यों को विस्तारित किया गया है। इससे लोगों की मदद करने का दायरा बढ़ गया है। **राज्यपाल राहत कोष की 18 वर्षों के अन्तराल में सन् 2002 के बाद 2020 में मैंने बैठक की।**

इस कोष का दायरा बढ़ाकर अब अकाल, बाढ़, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की सहायता के लिए कर दिया गया है।

साथ ही महामारी में औषधि व उपकरण हेतु सहायता, गंभीर रोगी को उपचार हेतु एक मुश्त सहायता, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को गंभीर बीमारी में सहायता, विपदाग्रस्त स्थितियों में असहाय बालक-बालिकाओं की चिकित्सा, भोजन व रख-रखाव में सहायता और किसानों को आपदा काल यथा सूखा, अतिवृष्टि और टिड्डियों के द्वारा फसल नुकसान में सहायता के लिए प्रस्तावित किया गया है। मेरे कार्यकाल के दौरान 56 लाख रुपये से अधिक की धन राशि दानदाताओं द्वारा दान की गई। जिसका मेरे द्वारा तत्काल सदुपयोग करते हुए कोविड-19 से लड़ाई में मदद करने हेतु 20 लाख रुपये प्रधानमंत्री केयर फण्ड, नई दिल्ली में, 20 लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष, राजस्थान में और 10 लाख रुपये की धन राशि पीपीई कीट एवं अन्य सामग्री क्रय किये जाने हेतु आर एम एस सी एल को उपलब्ध कराई गई।

मैंने इस हेतु एक माह का वेतन दान देते हुए प्रत्येक माह का 30 प्रतिशत वेतन भी ना लेने का निश्चय किया।

राज्य सरकार द्वारा कोरोना प्रभावितों को इन्जेक्शन उपलब्ध कराने को दृष्टिगत रखते हुए मैं पुनः आज 20 लाख रुपये की धन राशि प्रदान कर रहा हूँ।

कोरोना सभी के लिए खतरनाक है। प्रदेश की जनता को हर हाल में सुरक्षित रखना है। राज्य में कोरोना को हराने के लिए चिकित्सकों ने प्रभावी कदम उठाये हैं। राज्य में जागरूता के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

कोविड की लड़ाई में राज्य सरकार के साथ कन्धे से कन्धा मिलाते हुए मैंने अपने चिकित्सा कर्मियों, पुलिस कर्मियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों का हौसला बढ़ाया। यथा संभव सिविल सोसाइटी का सहयोग लेते हुए भीलवाड़ा तथा जनजातीय जिलों में सीधे आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराई गई।

मेरे द्वारा लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री से वार्ता करते हुए कोविड से बचाव के प्रयासों की समीक्षा की गई।

यहां के राज्य विश्वविद्यालयों का मैं कुलाधिपति भी हूँ। राज्य विश्वविद्यालयों को स्मार्ट बनाने के लिए कुलपतियों को मैंने निर्देश दिये हैं। राज्य विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोहों का समय पर आयोजन किया गया है। प्रत्येक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मैं शामिल हुआ हूँ। युवाओं के भविष्य का पूरा ध्यान रख रहा हूँ, इसलिए कोविड काल की विपरित परिस्थितियों में भी विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह ऑनलाइन आयोजित कराने की पहल की है।

कुलपति समन्वय समिति की बैठक 2016 के पश्चात 2019 में मेरे द्वारा बुलाई गई। अब प्रत्येक तीन माह में कुलपतियों से संवाद कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

कोरोना काल की विपरित परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया, जिसके द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुशंषाएं, लगभग उसी प्रकार की हैं, जैसी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा की गई है। इस कारण राजस्थान राज्य ऑनलाइन शिक्षण किये जाने की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम अद्यतिकरण, स्टेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेन्ट सिस्टम, च्वाइस वेस्ड क्रेडिट सिस्टम, केन्द्रीय मूल्यांकन पद्धति, विश्वविद्यालयों के आय का स्रोत बढ़ाने हेतु रोड मैप, विश्वविद्यालयों में ग्रउण्ड वाटर रिचार्ज सिस्टम बनाने इत्यादि पर भी लगातार निर्देश दिये गये, जिनका अनुपालन संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा है।

गत 26 नवम्बर को पूरे देश में 70 वां संविधान दिवस मनाया गया। आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान हमारा मार्गदर्शक है। हमारा मूल ग्रन्थ है। संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की मूल भावना का उल्लेख है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिये हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 क में हमारे द्वारा किये जाने वाले कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य, यह दोनों ही संविधान के प्रमुख स्तम्भ हैं। मौलिक अधिकारों की तो हम बात करते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हम हमारे कर्तव्यों को जानें, समझें और उनके अनुरूप ही अपना कार्य और व्यवहार करें। आमजन को संविधान की जानकारी होना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता, अखण्डता व सामाजिक समरसता के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। मैं चाहता हूँ कि विश्वविद्यालयों में युवाओं को मूल कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए अभियान चलाया जाये। प्रत्येक दीक्षांत समारोह में व अन्य कार्यक्रमों में, मैं उपस्थित युवा वर्ग को संविधान की प्रस्तावना और कर्तव्यों का वाचन करवा रहा हूँ। इससे छात्र-छात्राओं को संविधान में निहित कर्तव्यों का ज्ञान हो सकेगा। सभी विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान व संविधान स्तम्भ बनाये जा रहे हैं। राजभवन में भी विश्वविद्यालय उद्यान के साथ-साथ संविधान उद्यान, संविधान स्तम्भ तथा एक संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। जिससे पूरे राज्य की प्रतिकृति राज भवन में राजस्थान स्तम्भ के रूप में दिखाई देगी।

हमारा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पं. जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ. भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुषों की जन्म भूमि और कर्मभूमि है। इनके सिद्धांत और आदर्श हमारे प्रेरणास्रोत हैं। हम राष्ट्रपिता द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें और आने वाली पीढ़ी को भी इससे परिचित कराएँ। इसका छोटा सा प्रयास मैंने राजभवन में गांधीजी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान, 150 पौधों का रोपण और गांधी जी की प्रतिमा लगाकर किया। इसमें आम नागरिक और स्कूल के बच्चे शामिल हुए। अपने महापुरुषों की धरोहर को, उनके विचारों को, भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में ही हमारी सफलता निहित होती है।

मैं पिछले एक वर्ष में राज्य के 20 से अधिक जिलों का दौरा कर चुका हूँ। मैं बांसवाडा के सुदूर आदिवासी गांवों में भी गया। विश्वविद्यालयों द्वारा गोद लिये गए गांवों का भी मैंने दौरा किया। आवश्यकता है प्रतिभाओं को एक दिशा प्रदान करने की। यहां की उन्नति में अपना भी कुछ योगदान अर्पित कर सकूँ, यही मेरा प्रयास है। मैंने सीमावर्ती जिला जैसलमेर का दौरा किया। सैनिकों के साथ बैठा। बात की। उनके हाल चाल जाने। उनका हौसला बढ़ाया। सीमान्त क्षेत्रों, तनोट माता मन्दिर व भारत-पाक सीमा क्षेत्र का भी दौरा किया।

मेरी प्राथमिकता है कि प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो। इसके लिए हमें दिव्यांगों, बालिकाओं और महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। दिव्यांगों की हर संभव मदद के प्रयास करने हैं। उनको आगे बढ़ाने के अवसर देने होंगे। बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। गांव, शहर जहां भी ऐसी बालिकाएं जो विद्यालय नहीं जा पा रही हैं। उन्हें शिक्षा से जोड़ना है। नवजात शिशु और माताओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना मेरी प्राथमिकताओं में है।

मेरे द्वारा रेडक्रास के गठन के सम्बन्ध में सभी जिला अधिकारियों को जिला सम्बन्धी कमेटी के गठन के निर्देश दिये हैं ताकि राज्य स्तर पर भी रेडक्रास का विधिवत गठन कर निर्धारित कार्यों का संपादन कराया जा सके।

जनजातीय क्षेत्रों में कुल 40 गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने हेतु जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग को निर्देशित किया गया है। जनजातीय क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति व शैक्षणिक व चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने हेतु जनजातीय विकास विभाग को निर्देश दिये गए हैं।

सैनिक कल्याण बोर्ड की लगभग पांच वर्ष के पश्चात मेरी अध्यक्षता में बैठक सम्पादित हुई। इसमें फौज में जाने के लिए प्रोत्साहन राशि को पांच हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने, पूर्व सैनिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता 15 हजार से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने, पूर्व सैनिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोतरी करने और शौर्य पदक से अलंकृत सशस्त्र सेना के कार्मिकों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कराये जाने जैसे निर्णय लिये गये।

पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के साथ राजस्थान के पर्यटन विभाग का एमओयू कराया गया। जिसके अन्तर्गत राजस्थान के विभिन्न मेलों का प्रचार-प्रसार पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा किया जायेगा तथा कलाकारों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी। ताकि उन्हें ज्यादा पारिश्रमिक प्राप्त हो सके।

अंत में मैं अगले चार वर्षों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्र व राज्य सरकार एवं सीएसआर व सिविल सोसाइटी के सहयोग से प्राथमिकता के आधार पर कार्य किये जाने हेतु पन्द्रह बिन्दुओं का एक ऐजन्डा निर्धारित कर रहा हूँ। इससे राज्य सरकार के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में आम जनता को अधिकाधिक लाभ प्रदान किया जा सके।

धन्यवाद। जयहिन्द।